**[2025] 4 एससीआर 1734: 2025 आईएनएससी 565**

# मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अन्य

**बनाम**

# एस. ललिता और अन्य

(सिविल अपील संख्या 5528/2025)

24 अप्रैल 2025

**[दीपांकर दत्ता* और राजेश बिंदल, जे.जे.]**

## विचारणीय मुद्दा

यह मामला न्यायाधिकरण के समक्ष कर्मचारी के समय-बाधित आवेदन की रखरखाव से संबंधित है, जिसे सेवा विवाद में देरी से अभ्यावेदन की अस्वीकृति के बाद दायर किया गया था।

## शीर्ष टिप्पणियां

**प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 - धारा 20, 21 - सीमा की अवधि - उत्तरदाता - सरकारी कर्मचारी को 2010 में संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना-एमएसीपी के तहत परिकल्पित वित्तीय उन्नयन का दूसरा लाभ और 2015 में तीसरा लाभ दिया गया - 2016 में अपीलकर्ता के समक्ष उत्तरदाता द्वारा अभ्यावेदन, मार्च, 2009 से एसीपी योजना के तहत दूसरे वित्तीय उन्नयन का लाभ देने और मार्च 2015 से एमएसीपी के तहत तीसरे वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्त करने की मांग करते हुए, - अभ्यावेदन की अस्वीकृति - चुनौती - न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकृत आवेदन,जिसे, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था - शुद्धता:**

**अभिनिर्धारित:** उत्तरदाता ने 2009 में देय, एसीपीएस के तहत वित्तीय उन्नयन के दूसरे लाभ के अनुदान का दावा 2016 के अंत में किया - उत्तरदाता ने आवेदन में अनुरोध नहीं किया और सेवा नियमों में विशिष्ट प्रावधान का संकेत नहीं दिया, जिसके बारे में उसने अपीलकर्ता से राहत मांगी थी - इसके अभाव में, किसी को इस आधार पर आगे बढ़ना होगा कि उसने उसपर लागू किसी भी सेवा नियम के तहत प्रदान किए बिना अपने दम पर किया था ,और यह एक गैर-सांविधिक अभ्यावेदन था - उत्तरदाता द्वारा सीमा की अवधि को बढ़ाया नहीं जा सकता था - अभ्यावेदन हालांकि सेवा को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक नियमों में प्रदान नहीं किया गया है, फिर भी आवश्यक और अनिवार्य हो सकता है जब नियोक्ता द्वारा पीड़ित लोक सेवक को निष्क्रियता के कारण या अन्यथा वैध सेवा लाभ प्रदान नहीं किया जाता है, और बनाना होगा

*रचयिता

शीघ्रता से - उन मामलों को छोड़कर जहां अपील/पुनरीक्षण /स्मारक/अभ्यावेदन पर अंतिम आदेश पारित किए जाते हैं, वैधानिक रूप से प्रदान किए जाते हैं, धारा 19 के तहत मूल आवेदन दाखिल करने की सीमा, और धारा 20, 21, कार्रवाई के कारण के संचय की तारीख और अभ्यावेदन की तारीख की निकटता को ध्यान में रखते हुए गणना की जानी चाहिए, और मूल आवेदन दाखिल करने के लिए एक वर्ष की अवधि को इस तरह के अभ्यावेदन की तारीख से छह महीने की समाप्ति की तारीख से गिना जाना चाहिए यदि नहीं उस पर आदेश पारित किए गए थे - कार्रवाई के कारण को अत्यधिक विलंबित अभ्यावेदन करके और इसके परिणाम की प्रतीक्षा करके स्थगित नहीं किया जा सकता है - यदि उत्तरदाता पीड़ित है तो उसके अधिकारों के प्रभावित होने के तुरंत बाद न्यायाधिकरण के समक्ष उपाय का लाभ उठाना चाहिए था - उसे विलंबित अभ्यावेदन के माध्यम से अपनी शिकायत को दूर करने के लिए इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं करना चाहिए था - इस तरह के विलंबित अभ्यावेदन को दाखिल करना, जिसे कुछ ही समय में खारिज कर दिया गया था, वाद कारण को स्थगित करने और सीमा की अवधि को बढ़ाने का प्रभाव नहीं था ताकि आवेदन को समय के भीतर दायर किया जा सके - आवेदन समय बाधित था और न्यायाधिकरण द्वारा इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था - उच्च न्यायालय ने भी इसकी संधार्यता की जांच करने में विफल रहकर कानून में गलती की - अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, और इसे एक बहुत ही विशेष मामला मानते हुए, उत्तरदाता को प्राप्त किसी भी अधिशेष राशि को वापस करने का कोई निर्देश नहीं है -

भारत का संविधान - अनुच्छेद 142, 15(3), 41. [पैरा 23, 24, 33-38]

## उद्धृत निर्णयजन्य विधि

*सी. जैकब बनाम भूविज्ञान और खनन निदेशक,* **2008 आईएनएससी 1133: [2008] 14 एससीआर 634: (2008) 10 एससीसी 115;** *भारत संघ बनाम एमके सरकार,* **2009 आईएनएससी 1288: [2009] 16 एससीआर 249: (2010) 2 एससीसी 59;** *भारत संघ बनाम एनएम राउत,* **2024 आईएनएससी 1042: 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3873 - प्रतिष्ठित।**

*भारत संघ और अन्य बनाम एस. रंजीत सैमुअल और अन्य,* **2022 आईएनएससी 340 : 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 368;** *उपाध्यक्ष, डीडीए बनाम नरेंद्र कुमार और अन्य,* **2022 आईएनएससी 276 : [2022] 4 एससीआर 480: (2022) 11 एससीसी 641;** *उत्तरांचल राज्य बनाम शिव चरण सिंह भंडारी,* **2013 आईएनएससी 560: [2013] 9 एससीआर 609: (2013)**

**12 एससीसी 179;** *भारत संघ बनाम चमन राणा,* **2018 आईएनएससी 230: [2018] 3 एससीआर 640: (2018) 5 एससीसी 798;** *उड़ीसा राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण दास,* **2023 आईएनएससी 619 : [2023] 10 एससीआर 1049 : (2023) 15 एससीसी 273;** *एस.एस. राठौर बनाम मध्य प्रदेश राज्य,* **1989 आईएनएससी 268: [1989] स.पे.1 एससीआर 43: (1989) 4 एससीसी 582;** *डीबी गोहिल बनाम भारत संघ* **(2010) 12 एससीसी 301;** *भारत संघ बनाम तरसेम सिंह,* **2008 आईएनएससी 930 : [2008] 12 एससीआर 104: (2008) 8 एससीसी 648 - का उल्लेख किया गया है।**

*बी. डी. कदम और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य,* **2017 एससीसी ऑनलाइन कर 4772 - का उल्लेख किया गया है।**

## अधिनियमों की सूची

प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985; केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008; भारत का संविधान।

## प्रमुख शब्दों की सूची

अस्पष्टीकृत देरी या लैच; संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति
योजना, 2008; सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना, 1999;
समय-वर्जित आवेदन; सेवा विवाद; केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण; सीमा की अवधि; संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना के तहत वित्तीय उन्नयन का दूसरा लाभ; एमएसीपी के तहत तीसरा वित्तीय उन्नयन; विवेकाधीन रिट उपाय; लोक सेवक; असाधारण शक्तियां; दलील की अनुपस्थिति; वाद कारण; वैध लाभ से वंचित; सीमाएँ; लगातार गलत; देर से अभ्यावेदन

## मामले की उत्पत्ति

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5528/2025

कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगलुरु के दिनांक 08.03.2018 के निर्णय और आदेश से डब्ल्यूपी संख्या 9171/2018 में

## अधिवक्तागण

*अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्ता :*

साहिल भलाइक, तुषार गिरी, सिद्धार्थ अनिल खन्ना, रितिक अरोरा, शिवम मिश्रा, सुश्री. गुलशन जहां, मुर्शलीन अंसारी, सेवा सिंह।

*उत्तदाताओं के लिए अधिवक्ता:*

एस एन भाट, वरिष्ट अधिवक्ता, डी पी चतुर्वेदी, तरूण कुमार ठाकुर, श्रीमती पार्वती भाट, अभय चौधरी एम, विवेक राम सुश्री. अनुराधा मुतत्कर।

## सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

**<u>निर्णय</u>**

## दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इस अपील में चुनौती कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगलुरु[1] दिनांक 8 मार्च, 2018[2] के एक संक्षिप्त आदेश के लिए है, जिसमें अपीलकर्ताओं द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत की गई रिट याचिका[3] को खारिज कर दिया गया था। अपीलकर्ताओं ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, बेंगलुरु[4] के 1 अगस्त, 2017 के एक निर्णय और आदेश से व्यथित महसूस किया, जिसके तहत उसने उत्तरदाता के मूल आवेदन[5] की अनुमति दी।

1. उच्च न्यायालय
2. आक्षेपित आदेश
3. डब्ल्यूपी संख्या 9171/2018
4. न्यायाधिकरण
5. ओए संख्या 2/2017

3. इस अपील को जन्म देने वाले निर्विवाद तथ्य, संक्षेप में ये हैं:

   a. उत्तरदाता 11 मार्च, 1985 को दूरदर्शन केंद्र, बैंगलोर में टीवी समाचार और फिल्म लाइब्रेरियन (पुस्तकालय और सूचना सहायक) के रूप में भर्ती हुए।

   b. 31 मई, 2002 को, अपीलकर्ता को पहली बार 9 अगस्त, 1999 से सुनिश्चित कैरियर

प्रगति 6 योजना, 1999 के तहत वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्त हुआ।

c. चूंकि एसीपी योजना में 12 और 24 साल की सेवा के बाद पदानुक्रमित पैमाने पर वित्तीय उन्नयन के लाभों की परिकल्पना की गई थी, इसलिए प्रतिवादी 11 मार्च, 2009 से दूसरी बार एसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्त करने का हकदार हो गया।

d. संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति 7 योजना, 2009 को 19 मई, 2009 से एसीपी योजना का स्थान लेते हुए लागू किया गया था।

e. एमएसीपी योजना में 10, 20 और 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर तत्काल अगले उच्चतर ग्रेड वेतन में नियुक्ति की परिकल्पना की गई थी। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि पूर्व में एसीपी योजना के तहत उन ग्रेडों में दिए गए उन्नयन को जो अब वेतनमान के विलय/6वें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतन के उन्नयन के कारण समान ग्रेड वेतन प्राप्त करते हैं, एमएसीपी योजना के तहत उन्नयन प्रदान करने के उद्देश्य से अनदेखा किया जाएगा।

f. एसीपी योजना और एमएसीपी योजना के बीच मूल अंतर यह प्रतीत होता है कि जबकि पूर्व योजना के तहत वित्तीय उन्नयन सेवा में अगले उच्च पदोन्नति पद के वेतनमान के लिए था

---

6.एसीपी योजना
7.एमएसीपी योजना

, बाद की योजना के तहत, वित्तीय उन्नयन केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2018 के कार्यान्वयन पर अधिसूचित वेतनमान में अगले उच्च ग्रेड वेतन के संदर्भ में था।

g. चूंकि उत्तरदाता को 1 सितंबर, 2008 तक उच्च पद पर पदोन्नत नहीं किया गया था, इसलिए उसे 10 अगस्त, 2010 के एक आदेश के माध्यम से एमएसीपी योजना [4,800/- रुपये के ग्रेड वेतन के साथ पे बैंड 2] में परिकल्पित दूसरा लाभ दिया गया था *, जो 1* सितंबर, 2008 से प्रभावी था।

h. नियत समय में, 11 जुलाई, 2015 से, प्रतिवादी को 18 नवंबर, 2015 के एक आदेश *के माध्यम से* एमएसीपी योजना [5,400 रुपये का ग्रेड वेतन] के तहत तीसरे वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया गया था।

i. उत्तरदाता ने निस्संदेह एमएसीपी योजना के तहत दूसरे और तीसरे वित्तीय उन्नयन का लाभ बिना किसी आपत्ति के प्राप्त किया।

j. 4 अक्टूबर, 2016 को, उत्तरदाता ने महानिदेशक, दूरदर्शन, तीसरे अपीलकर्ता (मूल आवेदन में 5 वें उत्तरदाता) को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, ताकि उसे 11 मार्च, 2009 से 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन के साथ एसीपी योजना के तहत दूसरे वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया जा सके और 11 मार्च, 2015के प्रभाव से ।

एमएसीपी योजना के तहत 7600 रुपये के ग्रेड वेतन के साथ तीसरे वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया जा सके।

k. इस तरह के अभ्यावेदन को 5 नवंबर, 2016 को उप निदेशक (एस.II)। द्वारा खारिज कर दिया गया था।

l. अपने अभ्यावेदन की अस्वीकृति को चुनौती देते हुए, उत्तरदाता ने न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया, जिसने जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 1 अगस्त, 2017[9] के निर्णय और आदेश के माध्यम से उसके मूल आवेदन [8] की अनुमति दी, जिसे बाद में उच्च न्यायालय द्वारा *आक्षेपित आदेश* के माध्यम से पुष्टि की गई।

4. न्यायाधिकरण बी.डी. कदम और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के ***मामले में उच्च न्यायालय के 5 जून, 2017 के एक निर्णय और आदेश पर भरोसा करते हुए उत्तरदाता के ओ.ए. को अनुमति देने के लिए आगे बढ़े।*** [10].

5. आक्षेपित आदेश ने बीडी कदम (सुप्रा) ***में निर्णय के साथ अपनी सहमति दर्ज की*** और इस प्रकार, माना कि न्यायाधिकरण ने 5 नवंबर, 2016 के आदेश पर उत्तरदाता की चुनौती को बरकरार रखने में गलती नहीं की, जिसमें उसके अभ्यावेदन को खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने यह भी देखा कि ***बीडी कदम (सुप्रा) में निर्णय को भारत संघ द्वारा*** एसएलपी (सिविल) डी संख्या 29605/2017 की इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, लेकिन कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। तदनुसार, रिट याचिका में चुनौती को खारिज कर दिया गया था। हालांकि, उत्तरदाता की ओर से प्रस्तुत किया गया कि ट्रिब्यूनल के आदेश का अनुपालन किया

गया था, दर्ज किया गया था।

6. संयोग से, एसएलपी (सिविल) डी. संख्या 29605/2017 को *इस न्यायालय के 27 जनवरी, 2020 के एक आदेश* द्वारा खारिज कर दिया गया है।

7. इस स्तर तक, यह एक खुला और बंद मामला प्रतीत होता है। ट्रिब्यूनल ने बीडी कदम (सुप्रा) के आधार पर ओ.ए. की अनुमति देने के लिए आगे बढ़े , जिसका पालन करने के लिए वह बाध्य था, ट्रिब्यूनल के आदेश का पालन किया गया था

---

8 ओ.ए.
9 न्यायाधिकरण का आदेश
10 2017 एससीसी ऑनलाइन कर 4772

अपीलकर्ताओं ने उत्तरदाता को उसके द्वारा दावा किया गया लाभ प्रदान करके, और बीडी कदम (सुप्रा) में निर्णय के खिलाफ एसएलपी (सिविल) डी. संख्या 29605/2017 को खारिज कर दिया गया है, आगे कुछ भी विचार के लिए नहीं बचेगा। हालांकि, इस न्यायालय के निर्णयों सहित कुछ बाद के घटनाक्रमों को अपीलकर्ताओं द्वारा हमारे ध्यान में लाया गया है और यह आग्रह किया गया है कि यह न्यायालय इस तरह के घटनाक्रमों के आलोक में उत्तरदाता की पात्रता के मुद्दे की जांच कर सकता है और इसके बावजूद कि न्यायाधिकरण के आदेश का अनुपालन सुरक्षित किया गया है।

8. 27 जनवरी, 2020 को इस न्यायालय द्वारा एसएलपी (सिविल) डी. संख्या 29605/2017

को खारिज किए जाने के बाद, उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनर्विचार याचिका [11] दायर की गई थी। उच्च न्यायालय ने 7 मार्च, 2023 के अपने आदेश के माध्यम से पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। इस तरह की अस्वीकृति को चुनौती देते हुए, एसएलपी (सिविल) डी. संख्या 45401/ 2023 दायर किया गया है, जिसके बाद 8 दिसंबर, 2023 को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने

**भारत संघ और अन्य बनाम एस. रणजीत सैमुअल और अन्य और उपाध्यक्ष, *डीडीए वी. नरेन्द्र कुमार और अन्य।***[13] *में लिए गए निर्णयों के मद्देनजर नोटिस जारी किया है।*[12].

9. इसलिए, अपीलकर्ताओं का तर्क है कि यह मुद्दा अभी भी बड़े पैमाने पर है कि क्या उत्तरदाता न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के समक्ष अपने दावे में सफल होने की हकदार थी।

10. चूंकि एसएलपी (सिविल) डी. संख्या 45401/2023 लंबित है, इसलिए इसे अपने गुण-दोष के आधार पर तय किया जाना चाहिए। हालांकि, एक से अधिक कारणों से (जिसे हमें यहां व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा न हो कि लंबित वाद पर इसका कोई प्रभाव पड़े), हम वास्तव में

---

[11] आरपी संख्या 345/2022
[12] 2022 आईएनएससी 340 = 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 368
[13] 2022 आईएनएससी 276 = (2022) 11 एससीसी 641

ऊपर उल्लिखित नोटिस जारी करने के तथ्य के आधार पर अपीलकर्ताओं की ओर से पेश किए गए तर्क से प्रभावित नहीं हैं ।

11. हालांकि अपीलकर्ताओं द्वारा उद्धृत नहीं किया गया है, हमने भारत संघ बनाम एनएम राउत ***14*** में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ की हालिया उत्पत्ति के निर्णय पर गौर किया है, जिसमें एमएसीपी योजना और उसमें संदर्भित निर्णयों पर पूरी तरह से विचार करने पर, उत्तरदाता-कर्मचारियों के पक्ष में दिए गए वित्तीय उन्नयन पर रोक लगा दी गई थी और अपील की अनुमति दी गई थी। हालांकि, हमने एक तथ्यात्मक असमानता देखी है जो कुछ महत्व की है। -कर्मचारियों को क्रमशः फार्मासिस्ट और अधीक्षक के रूप में कार्य करते हुए दो या चार साल की सेवा के बाद गैर-कार्यात्मक उन्नयन प्रदान किए जाने के बावजूद एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया था, और इस प्रकार स्थिर नहीं थे। इस न्यायालय ने ***एनएम राउत*** (सुप्रा) में माना कि एमएसीपी योजना के तहत गैर-कार्यात्मक उन्नयन और उसके बाद वित्तीय उन्नयन का ऐसा अनुदान एमएसीपी योजना के इरादे और उद्देश्य के विपरीत होगा। यह स्थिति पैराग्राफ 20 में जो देखी गई थी, उससे स्पष्ट है, जो इस प्रकार है:

> "20. एमएसीपीएस की उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, हम यह समझने में विफल रहते हैं कि हम वित्तीय उन्नयन को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं, जो फार्मासिस्ट या अधीक्षक के पदों पर दो या चार साल की सेवा पूरी करने पर दिया गया था, जैसा भी मामला हो, यह तय करने के उद्देश्य से कि सरकारी कर्मचारी एमएसीपीएस के तहत अगले वित्तीय लाभ का हकदार होगा या नहीं। फार्मासिस्टों या अधीक्षकों के रूप में दो या चार वर्ष की सेवा पूरी करने पर दिए गए वित्तीय उन्नयन की अनदेखी करना, योजना के इरादे और उद्देश्य, नियोजित भाषा के साथ-साथ दिए गए उदाहरणों/उदाहरणों के विपरीत होगा। ..."

12. इसलिए, यह स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं को गैर-कार्यात्मक उन्नयन प्रदान करने के बावजूद एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया-

[14] 2024 आईएनएससी 1042 = 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3873

दो या चार साल की सेवा पूरी करने पर उत्तरदाता कर्मचारियों , जैसा भी मामला हो, इस न्यायालय द्वारा एमएसीपी योजना के अनुरूप नहीं पाया गया था और हालांकि, जो लोग सेवानिवृत्त हो चुके थे और जो इस तरह के फैसले की घोषणा के एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले थे, उनसे वसूली का आदेश नहीं देते हुए, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उनकी पेंशन और वेतनमान 1 जनवरी 2025 से पुनर्निर्धारित किया जाए। . हमारे सामने उत्तरदाता ने दावा किया था कि 24 साल की सेवा पूरी होने पर वित्तीय उन्नयन के लाभों का दावा किया था, जो उसे वित्तीय उन्नयन प्रदान करने की तारीख से प्रभावी था, जो एसीपी योजना के संदर्भ में देय था, जिसमें देरी हुई और अंतराल में, एमएसीपी योजना ने हस्तक्षेप किया। इसलिए, इस न्यायालय ने **एन. एम. राउत (सुप्रा)** में उत्तरदाता-कर्मचारियों के खिलाफ अभिनिर्धारित किया यह कारण काफी अलग है, जबकि यह अपील एक अलग दृष्टिकोण की मांग करती है।

13. जैसा भी हो, आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप न करना हमारी समझ के आधार पर तार्किक निष्कर्ष है कि एसएलपी (सिविल) डी. संख्या 45401/2023 पर नोटिस जारी करने का कोई प्रासंगिकता नहीं है और यह कि ***एनएम राउत*** (सुप्रा) में निर्णय उत्तरदाता के नुकसान के लिए काम नहीं करता है; हालांकि, हम अपने निर्णय को यहां समाप्त नहीं करने का प्रस्ताव करते हैं, लेकिन कुछ और शब्द कहने का प्रस्ताव करते हैं, इसका कारण यह है कि अपीलकर्ताओं ने अपने प्रतिवाद में ओ.ए.की संधार्यता पर बिरोध जताया अपीलकर्ताओं के अनुसार, ओ.ए. समय-वर्जित था और इसे इस तरह खारिज कर दिया जाना चाहिए था।

14. उत्तरदाता ने ओ.ए. के पैराग्राफ 3 में इस प्रकार दलील दी थी:

> "3.परिसीमा: आवेदक आगे घोषणा करता है कि आवेदन प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 21 में निर्धारित सीमा अवधि के भीतर है क्योंकि आवेदक आवेदक के दावे के खिलाफ अनुलग्नक ए-11 दिनांक 5.11.2016 में 5वें उत्तरदाता द्वारा पारित आदेशों को चुनौती दे रहा है।

15. चूंकि 21 दिसंबर, 2016 को ओ.ए. सत्यापित किया गया था, इसलिए उत्तरदाता आश्वस्त था और तदनुसार, घोषणा की कि यह प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985/15 की धारा 21 में निर्धारित सीमा की अवधि के भीतर था।

16. न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों ने रखरखाव की आपत्ति पर फैसला नहीं सुनाया, हालांकि, कारणों और टिप्पणियों के लिए, इस तरह की आपत्ति हमें काफी सही प्रतीत होती है।

***17. सी. जैकब बनाम भूविज्ञान और खनन निदेशक[16], भारत संघ वी।***

***एम.के. सरकार[17], उत्तरांचल राज्य बनाम शिव चरण सिंह भंडारी[18]*** *और* ***भारत संघ बनाम चमन राणा***[19] इस अपील पर सामग्री वाले सेवा संबंधी विवादों में बासी शिकायतों के साथ विलंबित दृष्टिकोण पर इस न्यायालय के निर्णय हैं।

18. ***सी. जैकब*** (सुप्रा) में, इस न्यायालय ने कहा कि इसके सामने का मामला " अभ्यावेदन और राहत" का एक विशिष्ट उदाहरण था। सेवा समाप्त होने के बाद कर्मचारी 18 साल तक चुप रहा। एक ऐसा चरण आ गया था जब उनकी पिछली सेवा के संबंध में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। वर्ष 2000 में कर्मचारी ने जो अभ्यावेदन दिया था, उसमें उसने दावा किया था कि उसे सेवा में वापस ले लिया जाना चाहिए। 9 अप्रैल, 2002 के एक आदेश द्वारा उक्त अभ्यावेदन को अस्वीकार करने पर, उन्होंने अस्वीकृति के उक्त आदेश को कार्रवाई के कारण के रूप में संदर्भित करते हुए, सेवा लाभों का दावा करते हुए क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। विद्वान न्यायाधीश ने दावे की जांच की, जैसे कि यह समय पर किया गया एक जीवित

दावा था, उस सेवा  समाप्ति के लिए पूर्व में उचित जाँच किये जाने की  सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए  नियोक्ता की गलती पाई गई

---

15 1985 अधिनियम

16 2008 आईएनएससी 1133 = (2008) 10 एससीसी 115
17 2009 आईएनएससी 1288 = (2010) 2 एससीसी 59
18 2013 आईएनएससी 560 = (2013) 12 एससीसी 179
19 2018 आईएनएससी 230 = (2018) 5 एससीसी 798

और बर्खास्तगी को अवैध  घोषित किया गया था। लेकिन चूंकि कर्मचारी पहले से ही सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंच चुका था, विद्वान न्यायाधीश ने कर्मचारी को 18 जुलाई, 1982 से पेंशन की राहत प्रदान की, यह मानते हुए कि वह उस दिन सेवा से सेवानिवृत्त हो गया था। इस न्यायालय ने यह समझने में असमर्थता व्यक्त की कि विद्वान न्यायाधीश 2005 में दायर एक रिट याचिका में 1982 में समाप्ति को अवैध कैसे घोषित कर सकते हैं  और साथ ही 22 वर्षों के बाद शुरू की गई कार्यवाही में,यह साबित करने में विफल रहने के लिए कि 1982 में सेवा  समाप्ति  के पूर्व जाँच की गयी थी, के लिए खान और भूविज्ञान विभाग में कैसे दोष पाया जा सकता है,  जब जिस विभाग में कर्मचारी ने काम किया था, वह 1983 में ही बंद हो गया था और नए विभाग के पास उसकी सेवा का कोई रिकॉर्ड नहीं था।

19. **एम.के. सरकार** ***(सुप्रा)*** *के तथ्यों* से पता चलेगा कि उनकी सेवानिवृत्ति के 22 साल से अधिक समय बाद, और भविष्य निधि योजना के तहत अपनी बकाया राशि प्राप्त करने के बाद,

सेवानिवृत्त- उत्तरदाता ने एक अभ्यावेदन दिया था जिसमें अनुरोध किया गया था कि उन्हें पेंशन योजना का लाभ दिया जा सकता है, साथ ही, भविष्य निधि योजना के तहत प्राप्त राशि को वापस करने की इच्छा व्यक्त करते हुए (पेंशन के बकाया के खिलाफ समायोजन के माध्यम से जो देय हो जाएगा, पेंशन योजना को अपनाने के उनके अनुरोध को स्वीकार करने पर )। उक्त अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया था। इसलिए सेवानिवृत्त-उत्तरदाता ने 1985 के अधिनियम की धारा 19 के तहत एक आवेदन दायर करके केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण 20 का दरवाजा खटखटाया, जिसमें रेलवे प्रशासन को यह निर्देश देने की मांग की गई कि वह उसे पेंशन योजना में बदलने के विकल्प का प्रयोग करने की अनुमति दे। कैट द्वारा आवेदन का निपटारा यह निर्देश देते हुए किया गया कि सेवानिवृत्त उत्तरदाता के अभ्यावेदन पर

---

20 कैट

तर्कसंगत आदेश पारित करके निर्णय दिया जाए , जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि उसने दावे की योग्यता के आधार पर जांच नहीं की थी। सेवानिवृत्त- उत्तरदाता के दावे को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद कैट के समक्ष दूसरा मूल आवेदन दायर किया गया था। कैट ने इस दूसरे आवेदन को स्वीकार कर लिया और रेलवे को निर्देश दिया कि वह सेवानिवृत्त उत्तरदाता को पेंशन योजना का विकल्प चुनने की अनुमति दे और उसे वह राशि भी सूचित करे जो विकल्प का उपयोग करने पर वापस की जानी चाहिए। अधिकार क्षेत्र वाले संबंधित उच्च न्यायालय से रेलवे द्वारा असफल संपर्क किया गया था, जिसके बाद संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू किया

गया था। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में इस न्यायालय को पैराग्राफ 15 और 16 में निम्नानुसार अवलोकन करने का अवसर मिला:

15. जब एक "बासी" या "मृत" मुद्दे/विवाद के संबंध में एक विलंबित अभ्यावेदन पर विचार किया जाता है और निर्णय लिया जाता है, ऐसा करने के लिए अदालत/न्यायाधिकरण द्वारा एक निर्देश के अनुपालन में, इस तरह के निर्णय की तारीख को "मृत" मुद्दे या समय-बाधित विवाद को पुनर्जीवित करने के लिए कार्रवाई का एक नया कारण प्रस्तुत करने के रूप में नहीं माना जा सकता है। सीमा या देरी और लैच के मुद्दे पर कार्रवाई के मूल कारण के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए, न कि उस तारीख के संदर्भ में जिस पर अदालत के निर्देश के अनुपालन में आदेश पारित किया जाता है। न तो योग्यता की जांच किए बिना जारी किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए अदालत का निर्देश, और न ही इस तरह के निर्देश के अनुपालन में दिया गया निर्णय, सीमा का विस्तार करेगा, या देरी और लैच को मिटा देगा।
16. एक अदालत या न्यायाधिकरण, किसी दावे या अभ्यावेदन पर "विचार" का निर्देश देने से पहले यह जांचना चाहिए कि क्या दावा या अभ्यावेदन "जीवित" मुद्दे के संदर्भ में है या क्या यह "मृत" या "बासी" मुद्दे के संदर्भ में है। यदि यह "मृत" या "बासी" मुद्दे या विवाद के संदर्भ में है, तो अदालत/न्यायाधिकरण को मामले को समाप्त कर देना चाहिए और इस पर विचार या पुनर्विचार का निर्देशन नहीं करना चाहिए। यदि अदालत या न्यायाधिकरण गुणों की जांच किए बिना "विचार" को निर्देशित करने का निर्णय लेता है, तो उसे यह स्पष्ट करना चाहिए कि इस तरह का विचार सीमा या देरी और लैच से संबंधित किसी भी विवाद पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा। यहां तक कि अगर अदालत स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कहती है, तो यह कानूनी स्थिति और प्रभाव होगा।

20. ***शिवा चरण सिंह भंडारी*** (सुप्रा) और ***चमन राणा*** (सुप्रा) पदोन्नति प्रदान करने के लिए देर के दावों से उत्पन्न हुए। ***चमन राणा*** (सुप्रा) में, यह माना गया था कि इस न्यायालय द्वारा एक निर्णय की बाद की घोषणा

जीवन के एक नए पट्टे को उत्साहित नहीं कर सकता था या कार्रवाई का एक नया कारण प्रस्तुत नहीं कर सकता था जो अन्यथा स्पष्ट रूप से एक मृत और बासी दावा था। ***शिव चरण सिंह भंडारी*** (सुप्रा) से निम्नलिखित अंश उद्धृत किया गया था:

> "*29*. ... कुछ भी नहीं, यह कहा गया है कि सब कुछ रुक सकता है लेकिन समय नहीं, क्योंकि सभी एक तरह से समय के गुलाम हैं। सीमा प्रदान करने वाला कोई प्रावधान नहीं हो सकता है, लेकिन पदोन्नति से संबंधित शिकायत को किसी भी समय नया जीवन का पट्टा नहीं दिया जा सकता है।

इसके बाद यह अवलोकन किया गया कि न्यायालय द्वारा अभ्यावेदन सिंड्रोम (संलक्षण) के तौर-तरीकों के संबंध में सावधानी बरतनी होगी ताकि स्पष्ट रूप से मृत और बासी दावों को पुनर्जीवित किया जा सके, जैसा कि ***सी. जैकब*** (सुप्रा) में चर्चा की गई है।

21. हम में से एक (राजेश बिंदल, जे.), ***उड़ीसा राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण दास***[21] में समन्वय पीठ के लिए बोलते हुए, उपचार का लाभ उठाने में अस्पष्टीकृत देरी और ढिलाई के प्रभाव पर पर विचार करने का अवसर मिला। उस मामले में न्यायालय अधिकारों के अं तिम रूप से प्रकाशित अभिलेख को चुनौती देने से संबंधित था। किसी पक्ष को देरी या ढिलाई करने के विषय पर राहत न देने के क्षेत्र में कई उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए, यह माना गया कि अंतिम प्रकाशन के 46 (छियालीस) साल बाद दायर की गई एक रिट याचिका में काफी देर हो चुकी थी और उत्तरदाताओं /रिट याचिकाकर्ताओं को कोई राहत उपलब्ध नहीं कराई जा सकती थी।

22. हालांकि ***सी. जैकब*** (सुप्रा) और ***एम. के. सरकार*** (सुप्रा) में कानून को इस बात को ध्यान में रखते हुए घोषित किया गया था कि क्रमशः उच्च न्यायालय और कैट के आदेशों द्वारा "बासी" या "मृत" दावों पर विचार करने के निर्देश थे, और उसके बाद, दावों की अस्वीकृति ने मुकदमेबाजी के दूसरे दौर को जन्म दिया

21 2023 आईएनएससी 619 = (2023) 15 एससीसी 273

स्वीकृत है कि यहां न्यायाधिकरण के ऐसे किसी भी आदेश ने हस्तक्षेप नहीं किया। इस प्रकार, एक तथ्यात्मक असमानता है; फिर भी, इस पर ज्यादा कुछ नहीं बदलता है।

23. वर्तमान अपील के तथ्यों में, हम पाते हैं कि उत्तरदाता को अगस्त, 2010 में एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन का दूसरा लाभ प्राप्त हुआ था और यहां तक कि नवंबर, 2015 में उसके तहत तीसरा लाभ भी प्राप्त हुआ था। उन्होंने मार्च, 2009 में अक्टूबर, 2016 में एक अभ्यावेदन देकर एसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन का दूसरा लाभ देने का दावा किया। उत्तरदाता के लि ए सौभाग्य से, उसे अपने अभ्यावेदन का फैसला करने के लिए न्यायाधिकरण से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इसकी प्राप्ति के 32 दिनों के भीतर, उप निदेशक (एस.II) ने 5 नवंबर, 2016 को इस तरह के अभ्यावेदन को खारिज कर दिया। एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी द्वारा प्रयोग किया गया उचित परिश्रम, [जिसने अभ्यावेदन का फैसला करना अपना कर्तव्य समझा, लेकिन अन्यथा इसकी जांच नहीं करने का फैसला कर सकता था क्योंकि (i) एक "बासी" या "मृत" दावा उठाया गया था और (ii) उत्तरदाता ने सेवा में रहते हुए, बिना किसी विवाद के वित्तीय उन्नयन के लाभों को स्वीकार कर लिया था] उत्तरदाता द्वारा यह आग्रह करके अनुचित लाभ नहीं उठाया जा सकता है कि उपरोक्त में घोषित कानून तथ्यात्मक असमानताओं के कारण उसके मामले में निर्णय लागू नहीं होंगे।

24. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग में स्व-लगाए गए प्रतिबंध,

जो इस न्यायालय के न्यायिक उदाहरणों से विकसित हुए हैं, को यहां फिर से बताने की आवश्यकता नहीं है। यह कहने के लिए पर्याप्त है, अस्पष्टीकृत देरी या लैच को उन कारकों में से एक माना जाता है जो विवेकाधीन रिट उपाय लागू होने पर राहत से इनकार करने में महत्व ग्रहण कर सकते हैं। एक उपयुक्त मामले में, एक रिट अदालत अपनी असाधारण शक्तियों को लागू करने से इनकार कर सकती है यदि

आवेदक की लापरवाही या अपने अधिकार का दावा करने के लिए चूक अनुचित देरी या ढिलाई दूसरे पक्ष के प्रति पूर्वाग्रह के साथ मिलकर इस तरह के इनकार की गारंटी देती है।

25. हालांकि, हालांकि परिसीमा कानून रिट क्षेत्राधिकार पर लागू नहीं होते हैं, 1985 के अधिनियम के तहत विचारणीय सेवा विवादों के संबंध में धारा 21 में पता लगाने योग्य सीमा के कानून लागू होते हैं, जिसे धारा 20 के साथ पढ़ा जाता है। धारा 20 और 21 (प्रासंगिक सीमा तक) इस प्रकार हैं:

> ***"20. आवेदन तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि अन्य उपाय समाप्त न हो जाएं।***
> *(1) एक न्यायाधिकरण आमतौर पर एक आवेदन को स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि यह संतुष्ट न हो जाए कि आवेदक ने शिकायतों के निवारण के रूप में **प्रासंगिक सेवा नियमों के तहत** उसके लिए उपलब्ध सभी **उपायों** का लाभ उठाया था।*
> *(2 ) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, एक व्यक्ति को शिकायतों के निवारण के रूप में **प्रासंगिक सेवा नियमों के तहत** उसके लिए उपलब्ध सभी **उपायों** का लाभ उठाया गया माना जाएगा, -*
> *(अ) यदि सरकार या अन्य प्राधिकरण या अधिकारी या ऐसे नियमों के तहत ऐसा आदेश पारित करने के लिए सक्षम अन्य व्यक्ति द्वारा कोई अंतिम आदेश दिया गया है, तो शिकायत के संबंध में ऐसे व्यक्ति द्वारा पसंद की गई किसी अपील या अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया गया है; या*

(ब) *जहां सरकार या अन्य प्राधिकारी या अधिकारी या ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए अपील के संबंध में ऐसा आदेश पारित करने के लिए सक्षम अन्य व्यक्ति द्वारा कोई अंतिम आदेश नहीं दिया गया है, यदि ऐसी अपील को प्राथमिकता दी गई थी या अभ्यावेदन किया गया था, तो उस तारीख से छह महीने की अवधि समाप्त हो गई है जिस पर ऐसी अपील की गई थी या अभ्यावेदन किया गया था।*

(स) *उप-धारा (1) और (2) के प्रयोजनों के लिए, किसी राज्य के राष्ट्रपति या राज्यपाल या किसी अन्य पदाधिकारी को स्मारक प्रस्तुत करने के माध्यम से आवेदक के लिए उपलब्ध कोई भी उपाय उन उपचारों में से एक नहीं माना जाएगा जो उपलब्ध हैं जब तक कि आवेदक ने ऐसा स्मारक प्रस्तुत करने के लिए चुना न हो।*

(जोर दिया गया)

*"**21. परिसीमा**.—(1) एक न्यायाधिकरण एक आवेदन को स्वीकार नहीं करेगा, -*

*(अ ) ऐसे मामले में जहां धारा 20 की उप-धारा (2) के खंड (ए) में उल्लिखित अंतिम आदेश शिकायत के संबंध में किया गया है, जब तक कि आवेदन नहीं किया जाता है, उस तारीख से एक वर्ष के भीतर जिस तारीख को ऐसा अंतिम आदेश दिया गया है;*

*(आ) ऐसे मामले में जहां धारा 20 की उप-धारा (2) के खंड (बी) में उल्लिखित अपील या* अभ्यावेदन *किया गया है और छह महीने की अवधि समाप्त हो गई है, उसके बाद छह महीने की उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर, इस तरह के अंतिम आदेश के बिना समाप्त हो गई थी।*

*... ".*

26. एस.एस . राठौर बनाम मध्य प्रदेश राज्य***22*** में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने धारा 20 को नोट करते हुए, निम्नानुसार अवलोकन करने का अवसर दिया:

15. कई राज्यों में सरकारी कर्मचारियों के लिए आचरण नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक आदेशों को अदालत में चुनौती देने से पहले प्रशासनिक उपायों को समाप्त करने की आवश्यकता होती है। ...

16. अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित नियमों में लोक सेवकों पर लगाए गए दंड के आदेशों के खिलाफ अपील करने का प्रावधान है। कुछ नियम दूसरी अपील या संशोधन भी प्रदान करते हैं। <u>प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम की धारा 20 का तात्पर्य अनुशासनात्मक नियमों को प्रभावी बनाना है और इसके तहत उपलब्ध उपायों का समाप्त होना प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम के तहत दावों को बनाए रखने के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है।</u> केंद्र के सरकारी

कर्मचारियों के लिए प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना की गई है और कई राज्यों ने संबंधित राज्यों के कर्मचारियों के लिए अधिनियम के तहत ऐसे अधिकरणों की स्थापना पहले ही कर ली है। यह कानून जल्द ही प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 20 के तहत निर्धारित लाइन पर स्थापित होने जा रहा है।

(जोर दिया गया)

27. जैसा कि एस.एस. राठौर ***(सुप्रा) में उल्लेख किया*** गया है और जैसा कि अभी भी वर्तमान स्थिति है, लोक सेवकों को नियंत्रित करने वाले सेवा नियमों (आचरण, अनुशासन और अपील, छुट्टी, पेंशन, आदि से संबंधित नियम) में पहली अपील, दूसरी अपील (आमतौर पर नहीं), मूल/अपीलीय आदेशों के खिलाफ पुनरीक्षण, या स्मारकों (सामान्य रूप से नहीं) के प्रावधान हैं। दुर्लभ मामलों में, ऐसे नियम उन कार्यों के खिलाफ अभ्यावेदन का भी प्रावधान कर सकते हैं जो लोक सेवकों को प्रभावित करते हैं और उनके द्वारा कानून के अनुसार नहीं माना जाता है। किसी भी घटना में, भले ही सेवा नियम अभ्यावेदन के लिए प्रदान नहीं कर सकते हैं, ऐसे मामले हो सकते हैं (इसके बाद चर्चा की जानी है) जहां किसी अभ्यावेदन पर विचार करने और निपटाने में चूक या विफलता कैट को स्थानांतरित करने के दावे को जन्म दे सकती है।

28. इस मोड़ पर, हम इस स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं कि कैट के पास, असाधारण मामलों में, 1985 के अधिनियम की धारा 19 के तहत एक मूल आवेदन पर विचार करने की शक्ति है यदि आवेदक ने अपने पर लागू सेवा नियमों के तहत शिकायतों का निवारण के लिए उपलब्ध उपायों को समाप्त नहीं किया हो तो भी ।

22 1989 आईएनएससी 268 = (1989)
4 एससीसी 582

यदि इस बिंदु पर किसी अधिकार की आवश्यकता है, तो कोई लाभप्रद रूप से ***डीबी गोहिल बनाम भारत संघ***[23] में निर्णय का उल्लेख कर सकता है।

29. धारा 20 पर वापस आते हुए, उपधारा 2 सहपठित उपधारा 1 के शुरुआती शब्दों का तात्पर्य, जिसे हमने ऊपर उजागर किया है, संदेह का कोई तरीका नहीं छोड़ता है कि उसमें संदर्भित "उपचार" शब्द, जिसे संज्ञा के रूप में उपयोग किया जाता है, का अर्थ "उपचार" है जो प्रासंगिक सेवा नियमों के तहत शिकायतों के निवारण के लिए वैधानिक रूप से उपलब्ध हैं। हालांकि, ऐसे मामले में जहां सेवा नियम प्रतिनिधित्व करने की कोई गुंजाइश प्रदान नहीं करते हैं, पीड़ित लोक सेवक अभ्यावेदन के लिए प्रदान किए बिना, यानी एक गैर-सांविधिक अभ्यावेदन , और इसके निपटान की प्रतीक्षा किए बिना, सीधे कैट से संपर्क कर सकता है उस आदेश/कार्रवाई को चुनौती दे सकता है जिसने उसके अधिकार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है और उसे व्यथित कर दिया है; और, यदि अधिकारियों द्वारा विभागीय प्राधिकारियों के समक्ष उपचार की समाप्ति न होने के संबंध में कोई आपत्ति उठाई जाती है, तो इसका विरोध यह आग्रह करके किया जा सकता है कि सेवा नियम चुनौती के तहत आदेश/कार्रवाई के खिलाफ विभागीय अधिकारियों को अभ्यावेदन के माध्यम से कोई वैधानिक उपाय प्रदान नहीं करते हैं।

30. हालांकि, ऐसे असंख्य मामले हो सकते हैं जहां 1985 के अधिनियम द्वारा कवर किए गए लोक सेवकों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले औपचारिक आदेश मौजूद नहीं हो सकते हैं,

लेकिन उनके अधिकारों का प्रभाव नियोक्ता की चुप्पी या निष्क्रियता से उत्पन्न हो सकता है ताकि अन्यथा वैध लाभ प्रदान किया जा सके। ऐसे मामले में क्या उपाय उपलब्ध है? ऐसे मामलों में, यह अत्यंत वांछनीय है कि इस तरह के प्रभाव की ओर नियोक्ता का ध्यान आकर्षित करने के लिए लोक सेवक द्वारा पहले कदम उठाए जाएं।

---

[23] (2010) 12 एससीसी 301

मान लीजिए, एक लोक सेवक पदोन्नति के लिए देय है या वेतन वृद्धि के लिए देय है या किसी भी सेवा लाभ के लिए पात्रता का दावा करता है, जो उसके अनुसार, देय है, लेकिन नियोक्ता लोक सेवक को वह नहीं देने में चुप या निष्क्रिय रहा है जो उसे देय है। ऐसे मामलों में, किसी की शिकायत का समर्थन करने का एकमात्र तरीका नियोक्ता के ध्यान में लाने वाले अभ्यावेदन के माध्यम से है कि सेवा लाभ प्रदान करना, हालांकि देय है, पर विचार नहीं किया गया है और शिकायत का निवारण किया जाना चाहिए। यदि अभ्यावेदन प्राप्त करने के बावजूद और 1985 के अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) में उल्लिखित अवधि समाप्त होने के बावजूद शिकायत का निवारण नहीं किया जाता है, तो ऐसे मामलों में, कैट यह मानकर मूल आवेदन को खारिज नहीं कर सकता है कि अभ्यावेदन के माध्यम से उपाय सेवा नियमों में प्रदान नहीं किया गया है। हालांकि, लोक सेवक को सतर्क रहना होगा और इस बात का ध्यान रखना होगा कि वह अपने अधिकार के प्रभाव की तारीख से अपनी शिकायत का समर्थन करने के लिए अनिश्चित काल तक

इंतजार न करे। यदि वह अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करता है, तो वह अपने जोखिम पर ऐसा करता है।

31. या, एक ऐसा मामला लें जहां अभी तक कोई नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं है, अर्थात, सार्वजनिक रोजगार के लिए एक उम्मीदवार का मामला जो चयन प्रक्रिया में भाग लेता है लेकिन असफल हो जाता है। यदि उसे प्रक्रिया के संबंध में कोई शिकायत है और वह इसे चुनौती देना चाहता है, तो वह तीसरे पक्ष के अधिकारों के अर्जित होने से तुरंत पहले ऐसा कर सकता है; या, वह पहले अभ्यावेदन कर सकता है और यदि कोई प्रतिक्रिया या कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जो उसकी शिकायत का समाधान नहीं करती है, तो वह सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर 1985 के अधिनियम की धारा 19 के तहत कैट के समक्ष आवेदन कर सकता है। हालांकि, यदि देरी होती है और तीसरे पक्ष के अधिकार अर्जित होते हैं, तो देरी को समझाना होगा और माफी मांगी जानी चाहिए।

32. धारा 20 को पढ़ते हुए जैसा कि हमने एस.एस. राठौर ***(सुप्रा) और*** एमके सरकार ***(सुप्रा) द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शक प्रकाश के साथ ऊपर व्याख्या की है***, हमें यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या उत्तरदाता द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किया गया ओ.ए.समय से है या नहीं \

33. उत्तरदाता ने ओ.ए. में अनुरोध नहीं किया और सेवा नियमों में विशिष्ट प्रावधान का संकेत नहीं दिया, जिसके तहत उसने 4 अक्टूबर, 2016 को अभ्यावेदन दाखिल करके तीसरे अपीलकर्ता से राहत मांगी थी। इस तरह की दलील के अभाव में, किसी को इस आधार पर आगे बढ़ना होगा

कि उसने अपने ऊपर लागू किसी भी सेवा नियमों के तहत प्रदान किए बिना अपने दम पर अभ्यावेदन दिया था और इस अर्थ में, यह एक गैर-सांविधिक अभ्यावेदन था। उत्तरदाता द्वारा यह दावा करके सीमा की अवधि को बढ़ाया नहीं जा सकता था कि उसके गैर-वैधानिक अभ्यावेदन को अस्वीकार करने के परिणामस्वरूप न्यायाधिकरण में जाने की कार्रवाई का कारण प्राप्त हुआ।

34. कानूनी स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए, इस तरह के मामलों में जो महत्वपूर्ण मानता है, वह यह है कि क्या प्रतिनिधित्व जो किया गया है और अस्वीकार कर दिया गया है, जिसके बाद कैट के अधिकार क्षेत्र को लागू किया जाता है, आवेदक-लोक सेवक को नियंत्रित करने वाले सेवा नियमों में वैधानिक रूप से प्रदान किया जाता है। उप-धारा (1) के साथ 1985 के अधिनियम की धारा 20 के शुरुआती शब्दों को पढ़ना, जिसमें धारा 19 के तहत मूल आवेदनों पर विचार करने के लिए एक सामान्य पूर्व शर्त के रूप में अन्य उपलब्ध उपायों की समाप्ति की आवश्यकता होती है, उन उपायों को संदर्भित करता है जो अंतिम आदेशों के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए प्रासंगिक सेवा नियमों के तहत उपलब्ध हैं। यदि संबंधित सेवा नियमों में अंतिम आदेशों के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का उपबंध नहीं है, तो ऐसे उपबंध के अभाव के कारण पीड़ित आवेदक-लोक सेवक का उपचार सीधे कैट के समक्ष होगा

अपने हित के प्रतिकूल या पूर्वाग्रहपूर्ण प्राधिकारियों के आदेश/कार्रवाई को चुनौती देने में; और, ऐसे मामले में, एक मूल आवेदन को इस आधार पर यंत्रवत् अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए कि सभी "उपाय" समाप्त नहीं हुए हैं। हालांकि, यह नहीं कहा जा सकता है कि यदि प्रासंगिक सेवा नियमों में अभ्यावेदन  करने का प्रावधान है, तो उपलब्ध कराए गए उपाय को समाप्त करना होगा जब तक कि एक असाधारण मामला स्थापित नहीं किया जाता है। सेवा नियमों में किए गए प्रावधान, यदि बिल्कुल भी, एक वैधानिक अभ्यावेदन  करने के लिए, इस तरह के अभ्यावेदन  का समय और क्या अभ्यावेदन  एक "बासी" या "मृत" दावा उठाता है - ये सभी 1985 के अधिनियम के तहत परिसीमा के प्रश्न को तय करने के लिए प्रासंगिक हैं। हालाँकि, उप-धारा (2) के साथ पढ़े जाने वाले धारा 20 के शुरुआती शब्द एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की मांग करेंगे। जैसा कि पहले देखा गया है, सेवा को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक नियमों में प्रदान नहीं किया गया एक अभ्यावेदन अभी भी आवश्यक और अनिवार्य हो सकता है जब नियोक्ता द्वारा पीड़ित आवेदक-लोक सेवक को निष्क्रियता के कारण या अन्यथा से वैध सेवा लाभ प्रदान नहीं किया जाता है। ऐसे मामले में, पीड़ित आवेदक-लोक सेवक को वैध लाभ से वंचित करने की बात पर ध्यान आकर्षित करने के लिए अभ्यावेदन शीघ्रता से और तीसरे पक्ष के अधिकारों, यदि कोई हो, को प्राप्त करने से पहले किया जाना चाहिए। इस तरह का अभ्यावेदन तीसरे पक्ष के अधिकारों के अर्जित होने के बाद भी किया जा सकता है, लेकिन व्यथित आवेदक-लोक सेवक के ध्यान में आने के उचित समय के भीतर। उचित समय का गठन क्या होगा यह आवश्यक रूप से प्रत्येक विशेष मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा और तदनुसार निर्णय लिया जाएगा।

35. हमारा मानना है कि उन मामलों को छोड़कर जहां अपील/पुनरीक्षण/स्मारकों/अभ्यावेदन पर अंतिम आदेश पारित किए जाते हैं जो वैधानिक रूप से प्रदान किए जाते हैं,

1985 के अधिनियम की धारा 19 के तहत एक मूल आवेदन दाखिल करने के उद्देश्य से सीमा, उपर्युक्त निर्णयों और उसकी धारा 21 और 20 को ध्यान में रखते हुए, कार्रवाई के कारण के संचय की तारीख और अभ्यावेदन की तारीख की निकटता को ध्यान में रखते हुए गणना की जानी चाहिए, और मूल आवेदन दाखिल करने के लिए एक वर्ष की अवधि को छह माह की समाप्ति की तारीख से गिना जाना होगा इस तरह के अभ्यावेदन की तारीख से यदि उस पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। यह देखने की जरूरत नहीं है कि कार्रवाई के कारण को अत्यधिक देर से अभ्यावेदन करके और इसके परिणाम की प्रतीक्षा करके स्थगित नहीं किया जा सकता है। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि लगातार गलत होने के मामले में अलग-अलग विचार उत्पन्न होंगे, जिसे ***भारत संघ बनाम तरसेम सिंह***24 में इस न्यायालय के निर्णय के आलोक में तय किया जाना है।

36. जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस तरह के आधार पर, उत्तरदाता को एसीपी योजना के बजाय एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन का लाभ देने की अपीलकर्ताओं की कार्रवाई से व्यथित महसूस करने पर , उसके अधिकारों के प्रभावित होने के तुरंत बाद न्यायाधिकरण के समक्ष उपाय का लाभ उठाना चाहिए था। उसे देर से अभ्यावेदन के माध्यम से अपनी शिकायत को दूर करने के लिए इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं करना चाहिए था। इस तरह के विलंबित अभ्यावेदन को दाखिल करना, जिसे कुछ ही समय में खारिज कर दिया गया था, कार्रवाई के कारण को स्थगित करने और सीमा की अवधि को बढ़ाने का प्रभाव नहीं था ताकि समय के भीतर दायर

ओ.ए. को प्रस्तुत किया जा सके।

37. दोनों मंचों, यानी न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने इस तरह की गंभीर आपत्ति के बावजूद ओ.ए. की रखरखाव की आपत्ति पर फैसला नहीं सुनाया। हमने जो कारण बताए हैं, वे अप्रतिरोध्य निष्कर्ष की ओर ले जाएंगे

---

[24] 2008 आईएनएससी 930 = (2008) 8 एससीसी 648

कि ओ.ए. समय-वर्जित था और न्यायाधिकरण द्वारा इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने भी न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देने में विफल रहकर कानून में गलती की, इस आधार पर कि बीडी ***कदम*** (सुप्रा) में निर्णय ने इस मुद्दे को कवर किया, हालांकि, यह जांच किए बिना कि क्या ओ.ए. बनाए रखने योग्य (संधार्य ) था।

38. इस तरह नियम बनाने के बाद, हम एक महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उत्तरदाता 2018 में सेवानिवृत्त हो गया है। न्यायाधिकरण के आदेश को लागू कर दिया गया है और उसे कुछ वित्तीय लाभ प्राप्त हुए हैं। उसके जीवन के सर्दियों के वर्षों के दौरान, यह सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता आवश्यक हो जाएगी कि वह एक पूर्ण अस्तित्व के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए गरिमा और उद्देश्य का जीवन जी सके। संविधान के अनुच्छेद 15(3) में निहित उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, जो राज्य को *अन्य बातों के साथ-साथ महिलाओं के लिए विशेष उपबंध करने में सक्षम बनाता है और इसके अनुच्छेद 41 में* अन्य बातों के साथ-साथ

वृद्धावस्था *के मामलों में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य की नीति के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया* गया है। हम, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का उचित प्रयोग करते हुए और इस मामले को एक बहुत ही विशेष मामले के रूप में मानते हुए, प्रतिवादी को उसके द्वारा प्राप्त किसी भी अधिशेष राशि को उसकी पात्रता के अलावा वापस करने का निर्देश देने से बचते हैं।

39. तदनुसार, अपील को आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप किए बिना निपटाया जाता है।

*मामले का परिणाम:* अपील का निपटारा।

*शीर्ष टिप्पणियां :* निधि जैन द्वारा तैयार की गयी ।

**<u>यह अनुवाद शिव बचन यादव पैनल अनुवादक द्वारा किया गया</u>**